बेकारी

रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स नं० १५

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाअी प्रभुदास देसाअी

अंक ३२

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १० अक्तूबर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

आचार्य कृपलानीसे विनती

आचार्य कृपलानीने दिल्लीसे ता० ३०-९-'५३ को मुझे अेक लम्बा पत्र लिखा है। अिसके लिअे में अुनका आभारी हूं। अुन्होंने ता० २५–९–'५३ को बम्बअीमें अेक पत्रकार-परिषद्‌में पारडी सत्याग्रहके बारेमें जो कुछ कहा था, अुसके साररूप वक्तव्यकी अेक नकल भी अपने पत्रके साथ भेजी है और लिखा है कि "सत्याग्रहियोंको दरअसल जो कुछ कहना है, वह अिसमें अच्छी तरह आ जाता है।"

विशेष रूपसे वे कहते हैं कि "अुस वक्तव्यमें मैंने अेक बात नहीं कही है। वह यह कि श्री मोरारजीभाअीने धरमपुरमें जमीन देनेकी सूचना की है। मान लीजिये कि वह जमीन काफी अच्छी है। परन्तु मेरा यह कहना है कि तीनेक हजार परिवार पारडीसे अपने घरबार अुठाकर दूसरे तालुकेमें जायं, अिसके बजाय पारडीके कुछ जमींदार पासके तालुकेमें घासवाली जमीन ले लें यह ज्यादा आसान होगा।"

आचार्य कृपलानीने अपने वक्तव्यमें यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि खेड सत्याग्रहकी मांग दरअसल क्या है। यह सचमुच आनन्दकी बात है, क्योंकि अैसा करना बहुत जरूरी था। पत्रकार-परिषद्‌की रिपोर्ट अखबारोंमें छप चुकी है, अिसलिअे में अुसे यहां नहीं देता। अुसकी विवादास्पद भाषाको छोड़कर अुसमें कही गअी मुख्य बातें संक्षेपमें नीचे देता हूं। श्री कृपलानीजी अुसमें कहते हैं कि,

१. अैसा कहा जाता है कि आदिवासी किसान खानगी मालिकीके हक पर हमला करना चाहते हैं और जमीनका फिरसे बंटवारा कराना चाहते हैं। लेकिन यह बिलकुल गलत है।

२. काश्तकार अितना ही चाहते हैं कि जमींदार घासवाली जमीनका अमुक हिस्सा अनाज पैदा करनेके लिअे अलग निकाल दें। काश्तकार सिर्फ अैसी अलग निकाली हुअी जमीन पर खेती करनेकी अिजाजत ही चाहते हैं। और अिसके बदलेमें वे लोग जमींदारोंको पैदावारका जो भाग प्रथाके अनुसार लगानके रूपमें दिया जाता हो वह देनेके लिअे तैयार हैं। जमीन तो आज जिनके अधिकारमें है, अुन्हीं जमीदारोंकी मालिकीकी रहेगी।

३. अिसलिअे सत्याग्रहियोंकी मांग यह है कि आज लगभग ५० हजार अेकड़ जो घासवाली जमीन है, अुसका दसवां हिस्सा, यानी ५ हजार अेकड़ जमीन अनाजकी खेतीके लिअे अलग निकालकर काश्तकारोंको लगान पर अुठाअी जाय। अिसमें खानगी मालिकीके हक पर हमला करनेकी कोअी बात ही नहीं है।

४. अिस प्रश्नकी जड़में जायं तो पता चलेगा कि नअी आर्थिक व्यवस्थाने अिन गांवों पर चढ़ाअी की, अुसके पहले अिन गांवोंकी ज्यादातर जमीन आदिवासियोंकी ही थी। जमींदार तो अुसके बाद पैदा हुअे। परन्तु पारडीके आदिवासी अपनी जमीनके अिस मूल हककी मांग नहीं करते। वे जो जमीन अुन्हें मूलतः विरासतमें मिली हुअी थी, अुस पर केवल खेती करनेका ही हक मांगते हैं। और अिसके लिअे वे जमींदारोंको लगान भी देनेको तैयार हैं।

५. अिसके अलावा, खेड़ सत्याग्रहके नेताओंकी यह भी मांग है कि पारडी विभागके अिस संपूर्ण प्रश्नकी जांच करनेके लिअे अेक कमीशन नियुक्त किया जाय।

६. अैसी जांचके बारेमें श्री विनोबा भी सहमत हैं। और अुन्होंने यह भी नहीं कहा कि पारडीका सत्याग्रह भूदानके सिद्धान्तों या कार्यपद्धतिके खिलाफ है।

७. फिर भी भूमिदान-यज्ञके हिमायती समाजवादी पार्टीके सदस्योंके साथ जमींदारोंसे मिलकर ५ हजार अेकड़ जमीन लगान पर जोतनेके लिअे काश्तकारोंको दिला सकते हैं। वक्तव्यके शब्दोंमें कहूं तो "जहां तक मैं जानता हूं श्री जयप्रकाश नारायण और दूसरे समाजवादी कार्यकर्ताओंने भूमिदानकी पद्धतिसे ही काम किया है; और मैंने सुना है कि श्री रविशंकर महाराजने भी अिस समस्याको हल करनेके लिअे अैसा ही प्रयत्न किया, लेकिन अुसका कोअी नतीजा नहीं निकला।"

८. अिसलिअे सारी बातोंका निचोड़ निकाला जाय, तो झगड़ेका मुद्दा बहुत ही छोटा और मामूली-सा रह जाता है। और अगर दोनों तरफ प्रतिष्ठाकी रक्षाका सवाल न पैदा हो, तो यह मामला मैत्रीपूर्ण ढंगसे निबटाया जा सकता है।

अिस तरह थोड़ेमें श्री कृपलानीजीके वक्तव्यकी मुख्य बातें ये हैं। अिस परसे पाठक देखेंगे कि सारी बातोंका सार अिन दो बातोंमें आ जाता है:

१. पांच हजार अेकड़ जमीन अनाजकी खेतीके लिअे काश्तकारोंको लगान पर मिले, अैसा प्रयत्न करना चाहिये।

२. अिस सारे प्रश्नकी जांच होनी चाहिये।

अिनमें से जांचकी बात तो अैसी है कि चाहे तो समाजवादी पार्टी खुद ही जांचका काम अपने हाथमें ले सकती है और अुसकी रिपोर्ट जनता और सरकारके सामने पेश कर सकती है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अैसी जांच यथासंभव शास्त्रशुद्ध और निष्पक्ष हो, तो जनता अुस पर विश्वास करेगी। लेकिन अैसी जांच करनी ही हो, तो पहले यह साफ हो जाना चाहिये कि किस बातकी जांच करनी है। क्या अिस बातकी जांच करनी है कि पिछले ४–५ सालमें बम्बअीके काश्तकारी कानूनके मुताबिक लोगोंमें क्या काम हुआ और कितनी जमीनोंका कब्जा लिया गया? या आदिवासियोंका जमीन पर जो मूल मालिकी हक कहा जाता है, अुसके बारेमें और वह अुनके हाथसे कैसे निकल गया अिसके न्याय-अन्यायके बारेमें जांच करनी है? या अन्य किसी बातकी जांच करनी है? जो कुछ भी हो, जांच-समितिकी मांगके सम्बन्धमें स्पष्ट व्याख्या हो जाना जरूरी है।

www.vinoba.in

लेकिन मुख्य और महत्त्वकी मांग तो जमीनकी मानी जायगी। भूमिदानके रूपमें या अन्य किसी तरीकेसे पांच हजार अेकड़ जमीन गरीब आदिवासियोंको दिलवाओी जाय; और मैं तो अिस मांगका सार यह समझता हूं कि प्रजा-समाजवादी पार्टीके कार्यकर्ताओंके साथ मिलकर भूदानके कार्यकर्ता या सरकार यह जमीन आदिवासियोंको जमींदारोंसे दिलवा दें तो भी कोअी हर्ज नहीं।

अगर खेड़ सत्याग्रहका हेतु अूपरकी बात कहने और लोगों तथा सरकारके सामने अुसे रखनेका ही हो, तो वह हेतु अब पूरा हुआ माना जायगा। मैं मानता हूं कि अ० भा० प्रजा-समाजवादी पार्टीके नेताने अूपर जो कहा है, वह बम्बअीके अुनके सब साथियोंको मंजूर होगा।

अगर अैसा हो तो कहा जा सकता है कि सारी बातमें दोनों पक्षोंके बीच कोअी बड़ा फर्क नहीं रह जाता। पांच हजार अेकड़ जमीन लगान पर प्राप्त करना हो, तो अुसके लिअे काम शुरू हो जाना चाहिये। यानी अुसके लिअे भूदान-प्रवृत्ति फिरसे शुरू होनी चाहिये। परन्तु खेड़ सत्याग्रहने पारडी तालुकेमें जो वातावरण पैदा कर दिया है, वह अिस कामके लिअे अनुकूल नहीं माना जा सकता। और जैसा कि श्री विनोबाने अपने अेक प्रवचनमें हाल ही में कहा है, "पारडीमें भूदान-आन्दोलनसे कुछ लाभ नहीं हुआ, अैसा कहना ठीक नहीं है। जयप्रकाशजीके अेकाध प्रवाससे भूदानको प्रगति करनेका पूरा मौका मिला है, अैसा नहीं कहा जा सकता।" सरकार भी अपने तरीकेसे जमीन देनेकी तैयारी बता रही है। श्री कृपलानीजी जैसे लोग सरकारसे बात करके यह जान सकते हैं कि सरकारका यह कदम कहां तक अिस समस्याको हल करनेमें सहायक हो सकता है।

यह सब करनेके लिअे जरूरत अिस बातकी है कि अब पारडी सत्याग्रहके नेता तुरन्त अुसे समेट लें। अिस प्रश्नके शांतिपूर्ण हलके लिअे अुठाया जानेवाला यह पहला कदम होगा। अिसमें प्रजा-समाजवादी पार्टीको अपनी प्रतिष्ठाकी आड़ नहीं लेनी चाहिये। अगर मैं श्री कृपलानीजीसे विनती कर सकता होअूं, तो मेरी अुनसे नम्र विनती है कि वे खेड़ सत्याग्रह तुरन्त बन्द कर दें और सरकारके साथ बातचीत शुरू करें। तभी जमींदारोंमें भूदानकी प्रवृत्ति पुनः जारी करनेका अुचित वातावरण पैदा होगा, जिससे प्रजा-समाजवादी पार्टीके और दूसरे भूदानके कार्यकर्ता साथ मिलकर काममें लग सकें।

अैसा हो तो आजकी दुःखद स्थितिसे बाहर निकला जा सकता है और वहां गरीबोंके कल्याणके लिअे सब अपने-अपने ढंगसे जो काम करना चाहते हैं, वह फिरसे शुरू हो सकता है। श्री कृपलानीजी अपने पत्रमें मुझे लिखते हैं: "मैं चाहता हूं कि मित्र-गण व्यक्तियों और पार्टियोंको भूल जायं। क्या हम सब आपसमें मिलकर अिस बातकी सावधानी नहीं रख सकते कि गरीब आदिवासी अन्यायके शिकार न बनें? अिसलिअे मैं कांग्रेसके मित्रों और अेक समय जो बापूके साथ काम करते थे, अुन सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे भूल जायं — मेरे अतीत और वर्तमानको भूल जायं और अिस सवालके हलका रास्ता खोजें।"

मेरी प्रार्थना है कि श्री कृपलानीजी अिस मामलेको निबटानेका रास्ता खोजनेमें अूपरके ढंगसे सहायता करें। श्री विनोबाने अिस तरहकी सर्वपक्षीय और सर्वग्राह्य भूमिका पर ही अपना भूमिदान-आन्दोलन खड़ा किया है। अुसे फिरसे अुस रास्ते और अुस भूमिका पर ले जानेकी मैं श्री कृपलानीजीसे प्रार्थना करता हूं।

३-१०-'५३

(गुजरातीसे) मगनभाअी देसाअी

भूदान-यज्ञ क्यों और कैसे?

[मध्यप्रदेश सरकारने अपने राज्यमें भूदान-यज्ञ कार्यमें मदद देनेके लिअे बाकायदा अेक बोर्ड बनाया है। अिस बोर्डको शुरू करनेके अवसर पर अुसके अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णदास जाजूने जो व्याख्यान दिया अुससे नीचेका हिस्सा लिया गया है। भूदान-प्रवृत्तिमें काम करनेवाले तथा अन्य लोगोंको वह मददरूप होगा अैसी आशा है।

२-१०-'५३ — म० प्र०]

राजनीतिक स्वराज्य मिल जानेके बाद आम जनताको आर्थिक और सामाजिक स्वातंत्र्य मिलनेका प्रश्न देशके सामने जोरोंसे आया। राजनीतिक क्षेत्रमें हरअेक वयस्कको समान 'वोट' देनेका अधिकार प्राप्त होने व अमलमें आने पर आज जो चारों ओर आर्थिक और सामाजिक विषमता चल रही है वह सहन होना संभव नहीं रहा। सदियोंसे गरीबोंका शोषण हो रहा है और भारतके दारिद्र्यने अेक कहावतका रूप धारण कर लिया है। स्वराज्य मिलनेके बाद ६ वर्ष बीत जाने पर भी अुसकी रोशनी गरीबकी झोंपड़ीमें नहीं पहुंच पाओी है। अिस दशामें भारतकी आर्थिक समस्या हल करना सर्वोपरि काम हो गया है।

महात्माजीने अहिंसाकी विचारधाराके अनुसार स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयत्नके साथ-साथ आर्थिक पहलुओं पर भी जोर दिया था और गुलामीकी दशामें भी जो कुछ बन आया सो कुछ मात्रामें कर दिखाया। परन्तु स्वतंत्र हो जानेके बाद राजसत्ताधिकारी अपनेको अुस मार्गसे जानेमें असमर्थ पाने लगे।

जगतभरमें, विशेषतः पूर्वी जगतमें जो आर्थिक विषमता हटानेकी पुकार मच रही है अुसकी प्रतिध्वनि भारतमें भी गूंजने लगी। समस्याको सुलझानेके लिअे हिंसाके मार्गका अनुसरण करना अुपयुक्त और संभव नहीं था, श्रेयस्कर भी नहीं था। क्रांतिकारी कानूनमें भी कुछ हिंसा आ ही जाती है और अुसे लोकमतका आधार रहे बिना वह निभना भी कठिन है। अितनेमें अीश्वरने पूज्य विनोबाजी द्वारा भूदान-यज्ञका प्रारम्भ करवाया। अिस यज्ञमें जमींदारोंसे जमीन प्राप्त करना और अुसे भूमिहीनोंको देना यह तो अेक स्थूल अर्थात् बाह्य अंग है। मुख्य बात तो धर्मचक्र-प्रवर्तन अर्थात् अर्थसंबंधी नैतिक विचारधाराको देशमें दृढ़मूल करना है, ताकि भारत सदा अपने सारे प्रश्न अहिंसाके मार्गसे ही हल कर सके और सर्वोदयी समाजकी स्थापना हो सके। अब भूदान-यज्ञ काफी प्रगति कर चुका है और अुसका स्वरूप तथा अुसकी विचार-धारा समझदारोंके खयालमें आ गअी है।

पर बुद्धिमानोंके मनमें यह अेक शंका दीखती है कि क्या जमीनकी सारी समस्या भूदान-यज्ञसे पूर्ण रूपसे सुलझ जायगी? पिछले दो वर्षोंमें जमीनके बारेमें जो हकीकत हुअी है अुस ओर ध्यान देते हुअे हमें भूदान-यज्ञसे काफी आशा बंधती है। जिनके पास अधिक जमीन है, वे महसूस करने लगे हैं कि अब अधिक जमीन अुनके पास नहीं रहेगी। जमीन-बिक्रीका सिलसिला बड़े जोरोंसे चल रहा है और वह अब छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बिक्री होकर अुन्हींके हाथोंमें जा रही है, जो खुद अपने परिश्रमसे खेती करेंगे। जो दूसरोंकी जमीन काश्त करते हैं भविष्यमें बननेवाले कानूनके अनुसार अुनसे जमीन वापस नहीं ले सकेंगे, अिस खयालसे बड़े पैमाने पर जो बेदखली शुरू हो गअी थी, वह अब अनेक राज्योंमें मुलतबी हो गअी है और बंद भी होनेकी आशा है। प्लानिंग-कमीशनने यह सिद्धान्त मान लिया है कि जमीनके बारेमें सीलिंग मुकर्रर होकर अधिक जमीन किसीके पास न रहे। हैदराबाद राज्यकी विधान-सभामें अिस आशयके अेक विधेयक पर विचार हो रहा है। आगे पीछे अन्य प्रदेश, राज्योंको भी अैसा

www.vinoba.in

ही कुछ कदम अुठाना होगा। पूज्य विनोबाजी सीलिंगका सिद्धान्त नहीं मानते हैं। अुनका कहना है कि भारतमें 'फ्लोरिंग' चलना चाहिये। जो स्वयं किसानी करके अपनी आजीविका चलाना चाहे और जिसके पास आजीविकाके लिअे दूसरा साधन न हो, अुसे पेट भरने जितनी जमीन मिलनी चाहिये। जमीनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बंटवारेके लायक अभी जो वातावरण बन रहा है, अुसका कारण बहुतांशमें भूदान-यज्ञ ही मानना अुचित होगा। राज्य-सरकारें अिस काममें अपना हाथ प्रायः कानूनके जरिये ही बंटा सकती हैं। वैसे कानून बनानेकी अनुकूल परिस्थितिका निर्माण वेगसे हो रहा है। पर हमें मुख्य बात तो यह करनी है कि अर्थ-संबंधी और धनकी खानगी मालिकीके बारेमें जनताकी विचारधाराको ही बदलना है, ताकि देशमें नैतिक अर्थशास्त्रकी स्थापना हो सके। यह काम भूदान-यज्ञ और संपत्तिदान-यज्ञसे ही हो सकता है।

भूदान-यज्ञका काम पक्षातीत रखा गया है। साम्यवादी दल और अेकाध अन्य समुदायको छोड़कर अन्य सब पक्षवाले अिस यज्ञका समर्थन कर रहे हैं, यथाशक्ति सहयोग भी दे रहे हैं। अपेक्षा रखी गअी है कि वे जब अिस काममें सहयोग देते हैं, तो अपना-अपना पक्ष भूलकर सामान्य सामाजिक कार्यकर्ताके नाते काम करेंगे और अिससे अपने पक्ष विशेषका कोअी हित साधन करनेकी कोशिश नहीं करेंगे। वितरणका काम भी अिसी नीतिसे होगा। वह निष्पक्ष हाथोंमें रखनेका प्रयत्न किया जायेगा और जिनके सुपुर्द किया जायगा, वे निष्पक्ष भावसे ही काम करेंगे।

मैं यह महसूस करता हूं कि भूमि-वितरणके काममें दो बातोंकी हमें विशेष अड़चन होगी। अेक तो दानपत्रके साथ जोड़नेकी खसरा जमाबंदीकी नकल प्राप्त करना और दूसरी, अगर खेतका केवल हिस्सा दान दिया हो, तो अुसे नाप कर अलग टुकड़ा बनाना। यह काम दानदाताको या बोर्डको कर लेना बहुत मुश्किल होगा और अुसमें समय भी बहुत लगेगा। अिसलिअे वह सरकारी अधिकारी द्वारा ही होना ठीक रहेगा। अिसके अलावा, जिनको जमीन दी जायगी या बड़े-बड़े चकों पर जो किसान बसाये जायेंगे, अुनको सरकारकी ओरसे कुछ सुविधायें मिलना जरूरी होगा। अिनके बारेमें यह बोर्ड सोच-विचारकर अपने मंतव्य सरकारके सामने यथासमय पेश करेगा। आशा है कि सरकार वे सुविधायें अुपलब्ध कर देगी।

शराबबन्दी रद्द नहीं की जा सकती

मद्रास और बम्बअी राज्यमें संपूर्ण शराबबन्दी चल रही है। अैसी अपेक्षा थी कि दूसरे राज्य भी जल्दी ही अिस नीतिका अनुकरण करेंगे और सारे देशमें संपूर्ण शराबबन्दी हो जायगी। अगर अंग्रेजोंके जाने और केन्द्र तथा राज्योंमें राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके बाद महात्माजी दो-चार साल और जीवित रहते, तो देशमें अैसी संपूर्ण शराबबन्दी कभीकी हो गयी होती। सन् १९२० के बादसे, गांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेस जिस बातको लगातार कहती और करती रही, तथा शराबबन्दीके समर्थकों और कांग्रेसके स्वयं-सेवकोंने अुसके लिअे जो कष्ट अुठाये, अुनका खयाल करते हुअे यह जरूरी था कि कांग्रेस अिस विषय पर २५ साल तक जो प्रस्ताव पास करती आयी थी अुनका अमल करती। लेकिन अैसा नहीं हुआ। शासनकी बागडोर जिन राजनीतिक नेताओंके हाथमें आयी, अुन्हें सरकारी अधिकारियोंने आयमें कमी पड़नेका डर दिखाया और जिनका अिस बातमें स्वार्थ था, अुनके अिशारे पर अुक्त नेताओंको शराबबन्दीका कार्यक्रम स्थगित करनेके लिअे राजी कर लिया। दुर्भाग्यसे सरकार और कांग्रेसके सर्वेसर्वा पंडित जवाहरलाल नेहरूने भी राज्योंको यही सलाह दी कि वे अिस दिशामें धीमी गतिसे बढ़ें।

जिन राज्योंने शराबबन्दी कुछ मर्यादित रूपमें शुरू की थी, अुनकी चाल और धीमी पड़ गयी। अिसके सिवा, नीतिका अमल सख्तीसे नहीं किया गया, जिससे अुसमें अनेक दोषोंका प्रवेश हो गया और विरोधियोंको मौका मिल गया। वे अिन्हीं दोषोंका हवाला देकर शराबबन्दी खतम करनेकी मांग करने लगे।

अगर शराबबन्दी रद्द करनेके लिअे जो कारण पेश किये जाते हैं, अुनकी जींच ध्यानपूर्वक की जाय, तो वे ज्यादा देर तक टिक सकें, अैसे नहीं हैं। अगर अिन्हीं कारणोंका प्रयोग दूसरे प्रचलित कानूनोंके विषयमें किया जाय, तो बहुत विचित्र परिणाम निकलते हैं। अुदाहरणके लिअे, रिश्वतखोरी और चोरीकी बात लें। सब लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे यहां अिन दिनों रिश्वत-खोरी बढ़ी है। कितने लोगोंको यह दुःखद अनुभव आया है कि जब तक पर्याप्त रिश्वत न दी जाय, तब तक कागज अेक दफ्तरसे दूसरे दफ्तरमें, या अुसी दफ्तरमें अेक क्लर्कसे दूसरे क्लर्कके पास नहीं जाते। तो क्या रिश्वतखोरीके खिलाफ हमारे कानूनमें जो धारायें हैं अुन्हें रद्द कर देना चाहिये? छोटी और बड़ी चोरियां भी आज बढ़ती जा रही हैं, तो क्या अुन धाराओंको मंसूख कर देना चाहिये, जो चोरीके लिअे सजाका विधान करती हैं।

अभी कुछ दिन हुअे, आन्ध्रमें शराबबन्दीके सवाल पर बड़ी चर्चा होती रही। अैसा कहा गया कि आंध्र राज्य अपना खर्च नहीं अुठा सकेगा। अुसकी आय खर्चसे कम होगी। अिस घाटेकी पूर्ति कैसे की जाय, अिसकी खोज शुरू हुअी। लोगोंकी नजर शराबबन्दी पर गयी। अुन्हें लगा कि शराबबन्दी रद्द कर दी जाय, तो घाटेकी पूर्ति आसानीसे हो सकती है। अखबारोंमें और मंच पर अिस विषय पर काफी लिखा और कहा गया। अुससे करीब ५ करोड़ रुपयेकी आयका अनुमान लगाया गया; बहुत लोगोंको लगा कि अिससे खर्च भी पूरा किया जा सकेगा और जन-कल्याणकी नअी-नअी योजनायें भी जारी की जा सकेंगी। अुन्हें यह याद नहीं रहा कि हमारे दलित और विपन्न देशवासियोंके लिअे शराबबन्दी खुद जन-कल्याणकी अेक अुत्तम योजना है। वे यह भी भूल गये कि सन् १९३७ में मद्रासमें पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडलने शराबसे होनेवाली आयकी हानिकी पूर्तिके लिअे बिक्री-कर शुरू किया था, और अिस बिक्री-करसे होनेवाली आय प्रतिवर्ष बढ़ती चली गयी है।

संविधानमें शराबबन्दीके विषयमें जो कुछ कहा गया है, अुसका ठीक तौर पर अध्ययन किया जाय, तो तटस्थ व्यक्ति अिस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता कि जहां शराबबन्दी चल रही है, वहां अुसे रद्द करनेकी कोशिश करनेका किसी सरकारको अधिकार नहीं है। लेकिन यह तो कानूनज्ञों और न्यायाधीशोंके विचारकी बात है। जहां तक रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी बात है, देशके और खासकर आंध्रके सारे रचनात्मक कार्यकर्ता शराबबन्दी रद्द करनेके विरुद्ध हैं।

महात्माजीका स्मरण हमें बुद्धि और साहस दे कि हम अपने दुखी भाअियोंके अुद्धारके लिअे शराबबन्दीकी अिस लड़ाअीको जारी रखें और सफल करें।

(अंग्रेजीसे) **स्वामी सीताराम**

शराबबन्दी क्यों?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०-१०-० डाकखर्च ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

१० अक्तूबर १९५३

बेकारी

अभी कुछ दिनोंसे अिस विषयकी बहुत चर्चा हो रही है। यों यह समस्या नयी नहीं है। अिस समस्याके हलके रूपमें कांग्रेसने देशी अुत्पादन या स्वदेशीकी बात अिस सदीके शुरूमें ही लोगोंके सामने रखी थी। लेकिन अुसका रूप ठीक क्या हो, अिसका स्पष्टीकरण तो गांधीजीकी प्रतिभाने ही किया। गांधीजीने ही पहली बार यह साफ समझा कि पश्चिमी ढंगका अुद्योगीकरण हमारे लिअे बिलकुल निकम्मा सिद्ध होगा। अुन्होंने बेकारीकी अिस समस्याको देश-व्यापी प्रमाण पर सुलझाना शुरू किया, और अुसके लिअे जो कुछ करना आवश्यक था, अुसके प्रतीकके रूपमें सारे देशमें हाथ-कताअी और हाथ-बुनाअीका संघटन किया। गांधीजीने समझ लिया था कि अगर गांवोंके आर्थिक जीवनका पुनरुद्धार नहीं किया जाता, और ग्रामोद्योगोंको राष्ट्रके जीवनमें फिरसे अुनका केन्द्रीय स्थान नहीं दिया जाता, तो भारतका नाश अनिवार्य हो जायगा।

अुनका यह विचार क्रान्तिकारी था और आज भी है। दुनियाभरमें सब जगह लोगोंका यह खयाल है कि अैसे हरअेक देशके लिअे, जो गरीबी और बेकारी मिटाना चाहता है, अुद्योगीकरणकी जरूरत है। गांधीजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अिस गलत मान्यताका विरोध किया, अुद्योगीकरणके खिलाफ हमें चेतावनी दी, और हमारा ध्यान तथा प्रयत्न ग्रामोद्योगोंकी दिशामें मोड़ा। अुन्होंने अैसा क्यों किया? अिसलिअे नहीं कि वे हमें हमेशा गरीब रखना चाहते थे, न अिसलिअे कि अुन्हें कोअी नअी चीज पसन्द नहीं आती थी और न अिसलिअे कि अुनकी प्रकृति संन्यासीकी थी। अुनके खिलाफ अिस तरहकी अूपरी टीकाअें अुन लोगोंने की हैं, जिन्हें या तो अुनके विचार नापसन्द थे या जिन्होंने अुनका अध्ययन ही नहीं किया था। अगर गांधीजी अुद्योगीकरणके खिलाफ थे, तो अुसका कारण यही था कि अुन्होंने देख लिया था कि यद्यपि अुद्योगीकरणके जरिये कुछ देशोंने अवश्य असामान्य समृद्धि हासिल की है, किन्तु वह हमारे लिअे अुपयोगी नहीं होगा; क्योंकि हमारे जैसे देशमें, जहां काम करनेके लिअे मनुष्योंकी अतिरिक्त अधिकता है, और जहां अुद्योगोंको जहां तक बने खेतीके साथ-साथ, जब खेतोंमें काम नहीं होता, तब करना पड़ता है, अुद्योगीकरण अनुकूल नहीं हो सकता। अिसके सिवा, अुद्योगीकरणसे अेक ओर तो पूंजीपतिके हाथोंमें सत्ताका खतरनाक केन्द्रीकरण होता है, जिससे मजदूर आजादी और आनन्द खोकर गुलाम बनता है; और दूसरी ओर विभिन्न देशोंके बीच कच्चे माल और बाजारोंकी प्राप्तिके लिअे होड़ पैदा होती है, जिससे आन्तरराष्ट्रीय अशान्ति और युद्धको अुत्तेजन मिलता है। अुद्योगीकरणके खिलाफ ये बहुत सबल आक्षेप हैं, और अभी तक किसीने भी अुनका संतोषजनक अुत्तर नहीं दिया है। अब तो हमारे देशमें, खासकर गांधीजीकी मृत्युके बाद, लोकमत भी अिस विचार पर आरूढ़ होता जा रहा है कि अगर हम अपने लोगोंको पूरा काम देना चाहते हैं, तो हमें ग्रामोद्योगों और गृह-अुद्योगों पर जितना बने अुतना अधिक ध्यान देना चाहिये और बड़े पैमाने पर होनेवाले कारखानोंके अुत्पादनसे बचना चाहिये। अलबत्ता जहां वह अनिवार्य हो, वहां अुसका प्रयोग किया जा सकता है।

लेकिन जहां अेक तरफ यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहां अुसके खिलाफ यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस सरकारमें — जिससे हम अिस महत्त्वपूर्ण विषय पर गांधीजीके नेतृत्वका अनुगमन करनेकी अुम्मीद करते हैं — व्यवसाय और अुद्योगके मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारीने कुछ दिन पहले अेक वाद-विवादके दौरानमें, कौंसिल ऑफ स्टेट्समें, अखबारोंमें आयी रिपोर्टके अनुसार, यह मंतव्य प्रगट किया कि अुनका यह निश्चय बढ़ता जा रहा है कि सिर्फ अुद्योगीकरणसे ही शहरी और ग्रामीण बेकारीका सवाल हल हो सकता है। अिस अकाट्य हकीकतका खयाल करते हुअे कि यंत्रोंके अुपयोगमें मजदूरोंकी कमी अवश्य होती है, और यदि अुद्योगीकरण हम अितने बड़े प्रमाण पर करना चाहें कि अुसमें हमारे सब लोगोंको पूरा काम मिले, तो अिसके लिअे दुनियाकी तत्सम्बन्धी कच्ची अुपज और बाजारों पर हमारा पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिये, और अैसा नियंत्रण बेजोड़ सैनिक ताकत, साम्राज्यवाद और युद्धके बिना नहीं हो सकता — अिस हकीकतका खयाल करते हुअे अुक्त मंत्री महोदयका यह मंतव्य सचमुच बहुत अजीब मालूम होता है।

अैसी हालतमें, व्यवसाय और अुद्योग-मंत्रीकी अिस घोषणाके बावजूद अगर गांधीजीके बताये हुअे कारणोंके अनुसार हमारी यही राय है कि अुद्योगीकरण हमारी बेकारीका हल नहीं है, तो फिर यह सवाल अुठता है कि अपनी जनताके लिअे पूरा अुद्योग पानेका अुपाय क्या है। अिस प्रश्नका अुत्तर सिद्धान्तकी दृष्टिसे यही है कि हमें अुत्पादनके अैसे अुपायोंका अवलम्बन करना चाहिये, जो बड़े-बड़े यंत्रोंकी बजाय आदमियोंको काम दें। बम्बअी, मद्रास, कलकत्ता जैसे शहरोंकी किसी भी सड़क पर चले जाअिये, आपको अैसे कितने ही आदमी बेकार घूमते-फिरते दिखाअी देंगे, जिनके पास करनेको कुछ नहीं है। बड़े यंत्र अुन्हें मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अेक तो बड़े यंत्र अुनके बूतेके बाहर हैं, दूसरे अुनमें बहुत कम लोगोंको काम मिल सकता है। अुनके लिअे अैसे साधन चाहिये जिनके द्वारा वे छोटे-छोटे समुदायोंमें संघटित होकर सस्ते औजारोंकी मददसे अुपयोगी वस्तुओंका निर्माण कर सकें। बुनियादी तौर पर अिसी तरहकी योजनाकी आवश्यकता है। वह हमारे राष्ट्रीय जीवनके सामान्य ढांचेके भी अनुकूल है, क्योंकि हमारी जनता अिने-गिने शहरोंमें केन्द्रित नहीं है, वह असंख्य गांवोंमें फैली हुअी है। जरूरत यह मालूम होती है कि हम शहरोंमें और गांवोंमें अुत्पादनके अनेक छोटे-छोटे सहकारी पद्धति पर काम करनेवाले मंडल बनायें, जो अधिकांशमें सादे यंत्रोंकी मददसे मनुष्य-शक्तिका ही अुपयोग करेंगे। अिसके कारण अक्षमता पैदा होगी और हम बाबा आदमके जमानेमें जा पहुंचेंगे, अैसा डर रखनेका कोअी कारण नहीं है। आधुनिक विज्ञान और अिंजीनियरिंगका कौशल हमारे पास है जिसका अुपयोग अैसी नयी मशीनरीकी खोजमें किया जा सकता है, जो अिस तरहके कामके बोझको हलका कर दे और अुसे गृह-अुद्योगोंमें काम करनेवाले कारीगरोंके लिअे आनंददायी बना दे।

अिन कामोंमें सरकारका भाग कअी तरहकी मदद पहुंचानेका होना चाहिये। अुदाहरणके लिअे, वह शुरूमें अुनके लिअे आवश्यक पूंजी, तालीम, कच्ची अुपज प्राप्त करनेकी सुविधायें, और यंत्र आदि साधन दे सकती है। वह अुत्पादनकी अिन ग्रामोद्योगी पद्धतियोंके सुधारके लिअे शोधकी व्यवस्था करा सकती है। अुसे अिस बातकी सावधानी रखनी होगी कि बड़े पैमाने पर अुत्पादन करनेवाले भारतीय या विदेशी कारखानेदारोंकी प्रतियोगिताके कारण ये छोटे-छोटे सहकारी अुद्योग नष्ट न हो जायं। जूतोंके अुद्योगका अुदाहरण लीजिये, जो कि गृह-अुद्योगकी तरह किया जा

www.vinoba.in

सकता है। यदि अुसे गृह-अुद्योगकी तरह बढ़ानेका निर्णय किया जाय, तो संक्रमण कालमें जब कि अुसके लिअे लोगोंको तालीम देकर तैयार किया जा रहा हो और अुसमें सुधारकी कोशिश हो रही हो, बड़े पैमाने पर चलनेवाले जूता-अुद्योगको बता देना होगा कि वह अब अमुक अवधि तक ही चलेगा। अिस बीचमें फैक्टरी और हाथके बनाये हुअे मालकी कीमत, फैक्टरीके माल पर लेवी लगाकर और हाथके मालको आर्थिक मदद देकर, समान कर देनी चाहिये। अिसी तरहकी नीति विदेशसे आनेवाली और दूसरी चीजोंके विषयमें भी बरती जा सकती है। अिस नीतिसे केवल अुन चीजोंको मुक्त किया जाय, जो अभी भारतमें नहीं बन सकतीं।

अिसके सिवा, गृह-अुद्योग और ग्रामोद्योगोंसे अुनमें काम करनेवालोंको पूरा मेहनताना मिलने लगे, अिसके लिअे यह आवश्यक है कि कीमतोंका नियंत्रण किया जाय। आज मध्यम वर्गके शिक्षित लोग बेकारोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं, अुसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि अुनकी शिक्षा किताबी होती है और पढ़ने-लिखनेके सिवा अुन्हें कोअी दूसरा काम नहीं आता है। अुसका अेक बड़ा कारण यह भी है कि छोटे अुद्योगोंसे अुन्हें पर्याप्त आजीविका नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं कि वे गांवोंमें लौटें, तो खेती और ग्रामोद्योगोंको अधिक लाभकारी बनाना होगा। तो जो सरकार शिक्षित लोगोंको वापस गांवोंमें भेजना चाहती है, अुसे कीमतोंका दृढ़ नियंत्रण अवश्य करना चाहिये, ताकि अुन्हें ग्रामोद्योगोंसे आजीविका मिलने लगे। यह बहुत अजीब मालूम होता है कि जिस देशमें शिक्षितोंकी संख्या अितनी कम है, वहां अुनमें अितनी बेकारी हो। अुसका अेकमात्र कारण यही है कि ब्रिटेन या अमेरिकाकी तरह यहां शिक्षितोंको अैसे स्वतंत्र अुद्योग, जिनसे वे अपनी जीविका अुपार्जित कर सकें, प्राप्त ही नहीं होते। अगर अुन्हें अैसे अुद्योग मिलते होते, तो निश्चय ही वे सरकारमें या व्यापारी पेढ़ियोंमें नौकरियां नहीं ढूंढ़ते फिरते।

सरकार खुद काफ़ी बड़ी खरीदार है। अगर वह जहां तक संभव हो ग्रामोद्योगों और गृह-अुद्योगोंके ही मालका अुपयोग करनेकी नीति अख्तियार करे, तो यह भी अुन्हें मदद पहुंचाने और प्रोत्साहन देनेका अेक बड़ा तरीका हो सकता है।

बड़ी बात तो यह है कि सरकारका संचालन अैसे लोगोंके हाथमें होना चाहिये, जिन्हें ग्रामोद्योगों और गृह-अुद्योगोंमें पूरा विश्वास हो। अुसे राष्ट्रका सारा आर्थिक जीवन ग्रामोद्योगों और गृह-अुद्योगोंकी बुनियाद पर खड़ा करनेकी कोशिश करनी चाहिये। यह नयी आर्थिक व्यवस्था जब तक मजबूतीसे जम न जाय, तब तकके लिअे हो सकता है कि अुसे अिसकी रक्षाके लिअे 'लौह-दीवार' खड़ी करनेकी जरूरत पड़े और अगर अैसी जरूरत जान पड़े, तो अुसे अुसमें भी हिचकना नहीं चाहिये। जब तक वह अिस तरहके क्रांतिकारी कदम नहीं अुठाती, तब तक अपने लोगोंके लिअे पूरा काम-धन्धा मुहैया कर सकनेकी आशा बहुत ही कम समझना चाहिये।

(अंग्रेजीसे) भारतन् कुमारप्पा

भावी भारतकी अेक तसवीर

किशोरलाल मशरूवाला

कीमत १–०–० डाकखर्च ०–४–०

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १–४–० डाकखर्च ०–६–०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद–९

बापू और जमीनकी समस्या

जमीनकी समस्या शायद हमारे देशके सामने खड़ी आजकी सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा समस्या है। बापू अिसके प्रति बड़े जाग्रत थे और जब कभी मौका आया अुन्होंने अिस समस्या पर अपने विचार प्रकट किये।

६ फरवरी, १९३० के 'यंग अिंडिया' में लिखते हुअे अुन्होंने कहा था:

"अहिंसाके रास्तेमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे बीच अुन देशी हितोंकी मौजूदगी है, जो ब्रिटिश हुकूमतके कारण पैदा हुअे हैं। ये हित हैं देशके धनी लोगों, सट्टेबाजों, जमींदारों, कारखानेदारों और अैसे ही दूसरे लोगोंके। ये सब लोग हमेशा अिस बातको महसूस नहीं करते कि वे आम-जनताका खून चूस कर जी रहे हैं; और जब वे यह महसूस करते हैं, तब अपने ब्रिटिश मालिकों जैसे ही कठोर और निर्दय हो जाते हैं, जिनके हाथके खिलौने और दलाल वे सब हैं। . . . अुनके लिअे यह समझना कठिन नहीं होना चाहिये कि हमारे लाखों-करोड़ों देशबंधु भूखों मर रहे हों तब लाखों-करोड़ों रुपये जमा करना महापाप है; और अिसलिअे अुन्हें अपनी यह दलाली छोड़ देनी चाहिये। कोअी भी मालिक आज तक अपने वफादार अेजेन्टोंकी मददके बिना सफलतासे काम करते नहीं देखा गया है।"

अिसके बाद आया दांडी-कूच, नमक-सत्याग्रह, गांधी-अिर्विन करार और फिर आअी कराची-कांग्रेस, जिसमें बुनियादी अधिकारोंका प्रस्ताव पास हुआ। अिन सबने जमींदारोंकी युगों पुरानी शांतिको भंग कर दिया, जिनके प्रतिनिधि गांधीजीसे मिले और अपनी चिन्तायें गांधीजीके सामने रखीं। अुन्होंने यह कहते हुअे जमींदारोंका डर दूर कर दिया:

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिना सही कारणके मैं सम्पन्न वर्गोंकी खानगी मिल्कियत छीननेमें हिस्सा नहीं लूंगा। मेरा ध्येय आपके पास पहुंच कर आपका हृदय-परिवर्तन करनेका है, ताकि आप अपनी सारी खानगी मिल्कियत अपने काश्तकारोंके ट्रस्टियोंके नाते अपने पास रखें और मुख्यतः अुन्हींके कल्याणमें अुसका अुपयोग करें। . . ."
('सिलेक्शन्स फ्रॉम गांधी', पृष्ठ ८८)

लेकिन साथ ही गांधीजीने अुन्हें अेक चेतावनी भी दे दी:

"मैं आपसे कहूंगा कि **आपकी जमीन पर जितना अधिकार आपका है, अुतना ही आपकी रैयतका भी है**। आप अपना पैसा अैश-आराम या तड़क-भड़कका जीवन बितानेमें नहीं अुड़ा सकते; वह पैसा आपको अपनी रैयतके भलेके लिअे खर्च करना चाहिये। अेक बार अगर आपने अपनी रैयतको आपके साथ पारिवारिक संबंध अनुभव करने दिया और यह विश्वास दिला दिया कि परिवारके सदस्योंके नाते अुनके हितोंको आपके हाथों कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आप निश्चित मानिये कि अुनके और आपके बीच न तो कोअी संघर्ष होगा और न वर्ग-विग्रहकी नौबत आयेगी।"
(बड़ा टाअिप हमारा है) ('सिलेक्शन्स फ्रॉम गांधी', पृष्ठ ८९)

बापूके शब्दोंमें अेक आदर्श जमींदार गांवोंके गलत नामसे पुकारे जानेवाले भारतके गोबरके ढेरोंको आसानीसे 'शांति, स्वास्थ्य और सुखके धामों' में बदल सकता है, बशर्ते:

"वह अपनी रैयतके घनिष्ठ संपर्कमें आवे, अुनकी जरूरतोंको जाने और अुन्हें निर्जीव बनानेवाली निराशाके बदले अुनमें आशाका संचार करे। वह खुद गरीब बन जायगा, ताकि अुसकी रैयतके जीवनकी जरूरतें पूरी हो सकें। वह

www.vinoba.in

अपनी देखभालमें रहनेवाली रैयतकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन करेगा, अुन्हें शिक्षा देनेके लिअे स्कूल खोलेगा, जिनमें वह रैयतके बच्चोंके साथ ही अपने बच्चोंको भी शिक्षा दिलायेगा। वह गांवके तालाव और कुओंको शुद्ध करेगा। वह खुद सड़कें और पाखाने साफ करके, रैयतको अपनी सड़कें और पाखाने साफ करना सिखायेगा।" (यंग अिंडिया, ५-१२-'२९)

अिस तरह वे चाहते थे कि जमींदार किसानोंको अपने परिवारके सदस्य मानें। जमीनकी मालिकीके बारेमें बापूके विचार बिलकुल स्पष्ट थे। मअी १९३९ में वृन्दावन (विहार) नामक स्थान पर अेक सार्वजनिक सभामें अिकट्ठे हुअे किसानोंसे अुन्होंने कहा था:

"मैं मानता हूं कि **जो जमीन तुम जोतते हो अुस पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिये।** लेकिन वह अेकदम तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम अुसे जमींदारोंसे जवरन् नहीं ले सकते। **अिसका अेकमात्र रास्ता अहिंसा है,** अपनी शक्तिको पहचानना है।" (मोटे टाअिप हमारे हैं) (हरिजन, २०-५-'३९)

अेक दूसरे स्थान पर अुन्होंने कहा है:

"सच्चा समाजवाद हमें अपने पुरखोंसे विरासतमें मिला है, जिन्होंने हमें सिखाया है — **सबै भूमि गोपालकी।** फिर सीमारेखा कहां है? आदमी ही अुस रेखाका वमानेवाला है, अिसलिअे वह अुसे मिटा भी सकता है। गोपालका शाब्दिक अर्थ है गायें पालनेवाला; अुसका अर्थ अीश्वर भी है। आजकी भाषामें अुसका अर्थ है राज्य यानी जनता। अिस बातको सिद्ध कर दिखानेकी जरूरत नहीं कि आज जमीन जनताके अधिकारमें नहीं है।" (हरिजन, २-१-'३७)

अब जनता — लोग — फिरसे जमीनके मालिक कैसे बनें? बापूको पक्का विश्वास था कि वे फिरसे जमीनके मालिक बनेंगे:

"अिस बारेमें मुझे कोअी शक नहीं कि हम अिस समस्याका वैसा ही अच्छा हल खोज सकते हैं, जैसा कि दूसरा कोअी राष्ट्र खोज सकता है, अिसमें रूस भी शामिल है। और अैसा हम बिना हिंसाके कर सकते हैं।... **जमीन और सारी जायदाद अुसकी है, जो अुस पर काम करे।** (मोटे टाअिप हमारे हैं) (हरिजन २-१-'३७)

अिस हलकी अेक झलक हमें आगाखान महलमें हुअी बापू और मीराबहनकी बातचीतसे मिल सकती है। मीराबहनने अेक दिन बापूसे पूछा: "स्वराज्यके बाद जमीनका बंटवारा कैसे किया जायगा?"

बापूने जवाब दिया: "जमीन पर राज्यका अधिकार होगा। मैं मानता हूं कि स्वराज्यमें शासन अैसे लोगोंके हाथमें होगा, जो अिस आदर्शमें श्रद्धा रखते हैं। **अधिकतर जमींदार स्वेच्छासे अपनी जमीनें छोड़ देंगे।** जो अैसा नहीं करेंगे, अुन्हें कानूनके मातहत अैसा करना पड़ेगा। (मोटे टाअिप हमारे हैं) (हरिजन, २९-१२-'५१)

थोड़ेमें, अूपरके अुद्धरणोंसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि बापू तीन सिद्धान्तोंके आधार पर भारतकी भूमि-समस्या हल करना चाहते थे:

१. 'सबै भूमि गोपालकी';
२. जमीन और सारी जायदाद अुसकी है, जो अुस पर काम करे;
३. जमींदार स्वेच्छासे अपनी जमीनें छोड़ देंगे। अहिंसक कार्यकर्ताका ध्येय हमेशा जमींदारोंका हृदय-परिवर्तन करनेका होना चाहिये।

बड़े आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि आचार्य विनोबाके भूदान-यज्ञ आन्दोलनके ये ही तीन वुनियादी सिद्धान्त हैं। शायद अिसीलिअे विनोवा कहते हैं कि भूदान-यज्ञ बापूका ही काम है, और वे जीवनभर बापूका ही काम करते रहे हैं। आगामी गांधी-जयन्तीके दिन हम रचनात्मक कार्यकर्ता अपने दिलोंको टटोलें और अपने आपसे पूछें: "हमें बापूका नाम प्यारा है या काम? अगर हमें अुनका काम प्यारा है, तो भूदान-यज्ञके लिअे हम क्या कर रहे हैं?"

अिलाहावाद, २१-९-'५३ **सुरेश रामभाअी**
(अंग्रेजीसे)

गांधी, कीन्स और चरखा

पश्चिमके लोग गांधीको यंत्र-विज्ञानकी प्रगतिका शत्रु समझते रहे हैं, गोया कोअी पुरानी चालका रमता जोगी हाथमें चरखा लिये घूमता-घूमता २०वीं सदीमें निकल आया हो।

अुनके मन पर पड़ी हुअी गांधीकी यह छाप कितनी सही है? गांधीने कभी अर्थशास्त्री होनेका दावा नहीं किया। आर्थिक सवालोंके प्रति अुनका दृष्टिकोण अुनके दर्शनकी पृष्ठभूमिके प्रसंगमें ही समझा जा सकता है।

अुनके मतानुसार विदेशोंके साथ व्यापार, औद्योगिक सम्बन्ध, व्यापारी पेढ़ियोंके परिमाण और अुनके स्थान, या किसी भी आर्थिक कार्यके निर्णयकी अेक ही कसौटी थी: वह हिंसाकी संभावनाको बढ़ाता है या कम करता है? सभ्यताकी मापका अुनका यही मापदण्ड था।

अिस वृत्तिका अेक अुदाहरण लीजिये; सन् १९५० में अखिल भारत कांग्रेस कमेटीने 'हमारा तात्कालिक कार्यक्रम' नामकी अेक पुस्तिका प्रकाशित की थी। अिस कार्यक्रमका, जो कि अुसने अपनी सिफारिशके साथ योजना-कमीशनको सौंपा था, अेक मुख्य अुद्देश्य 'मानव व्यक्तित्वका सर्वांगी विकास' बताया गया था।

किसी आर्थिक कार्यक्रममें, जिसके अुद्देश्योंमें पूंजीके निर्माण और खादके लिअे मृत पशुओंके अुपयोग आदि विषयोंकी चर्चा हो, मानव-व्यक्तित्वके सर्वांगी विकासकी वात भी कही जाय — तो पश्चिमके लोगोंको यह चीज बड़ी अटपटी मालूम होगी।

अिस तरह गांधी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ भी थे और आदर्शवादी व्यक्ति भी थे। अुन्होंने खुद कहा है कि "मैं कोअी स्वप्नसेवी पागल नहीं हूं, व्यावहारिक आदर्शवादी हूं।"

२

मेरा खयाल है कि गांधीके विषयमें पश्चिमके लोगोंकी अुक्त धारणाका आधार अुनका प्रारम्भिक जीवन है, जबकि गांधी आधुनिक सभ्यताकी सारी चीजोंकी निन्दा करते थे।

बादमें गांधीने प्रचलित सभ्यताके लाभोंके खिलाफ अपने विरोधमें कुछ संशोधन कर लिया था। तब भी यह सवाल रह जाता है कि क्या चरखेके विषयमें अुनके अुत्साहमें, बड़े अुद्योगोंके विरोधमें और भारतीय किसानों तथा भारतीय गांवोंको ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाये रखनेमें, वस्तुस्थितिके दर्शनकी कमी प्रगट होती है।

अिस प्रश्नका अुत्तर देनेके पहले गांधीकी जीवन-दृष्टि और भारतीय परिस्थितियोंसे सम्बद्ध दो मान्यतायें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिये।

पहली मान्यता यह है कि आर्थिक प्रवृत्तिका अंतिम अुद्देश्य अैसी परिस्थितियोंका निर्माण करना है, जो मनुष्यकी आध्यात्मिक अुन्नति, अुसकी स्वतंत्रता, व्यक्तित्वके विकास और कर्तव्य-बोधमें ज्यादासे ज्यादा अनुकूल हों।

www.vinoba.in

दूसरी मान्यता यह है कि आलस्य और बेकारीकी अथवा आर्थिक स्वाधीनताके सम्पूर्ण अभावकी स्थितिमें अिन अुद्देश्योंकी सिद्धि नहीं हो सकती।

अिन मान्यताओंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सारी आर्थिक समस्याओंमें बेकारी सबसे ज्यादा गम्भीर सवाल है और अैसा मालूम होता है कि गांधीने अिस बुराअीको दूर करनेका संकल्प कर लिया था।

३

आगे बढ़े हुअे अुद्योग-प्रधान देशोंमें ज्यादा सुधरे हुअे यंत्रों और बेहतर संघटनसे आय बढ़ती है, कीमतें कम होती हैं और सप्ताहमें कामके दिन घटते हैं।

यंत्रोंमें हुअी अुन्नतिसे जो अस्थायी बेकारी अुत्पन्न होती है, अुसे लोगोंको दूसरे धंधोंमें जानेके लिअे प्रोत्साहन और आवश्यक तालीम देकर दूर कर दिया जाता है।

अिसलिअे स्व० लार्ड कीन्स और 'सब लोगोंको पूरा काम-धन्धा' देनेकी अर्थनीतिके अुनके अनुयायियोंने अपना ध्यान असंबद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थासे होनेवाली बेकारी पर ही केन्द्रित किया।

अैसा माना जाता था कि वह राष्ट्रकी आय और खर्चके वितरणमें संतुलनके अभावसे पैदा होती है, क्योंकि अुससे मांगमें कमी आती है और बचतमें बढ़ती होती है। अिस परिस्थितिके सुधारके लिअे खर्च बढ़ाना चाहिये, व्यर्थ पड़ी हुअी बचतको खींचकर व्यवसायोंमें नियोजित करना चाहिये और बेकार पड़ी हुअी मशीनोंका अुपयोग करना चाहिये।

कीन्सके नये अर्थशास्त्रका सम्बन्ध मुख्यतः अुत्पादनकी अतिरिक्त क्षमता और सरकार तथा अुद्योगों द्वारा बचतका अुत्पादक कामोंमें अुपयोग करनेकी अपर्याप्त मांगसे ही था।

किन्तु हिन्दुस्तानकी बेकारीमें पश्चिमी ढंगके अिस अर्थ-रचनागत असंतुलनका बहुत कम हाथ है। अुसकी बेकारी अेक अलग किस्मकी है।

४

भारतकी ३६ करोड़ आबादीमें प्रति ५ आदमियोंमें से ४ की जीविकाका आधार खेती पर है। औद्योगिक मजदूरोंका अेक बहुत छोटा हिस्सा बड़े पैमाने पर चलनेवाले अुद्योगोंमें काम करता है।

खेतीका काम मौसम पर ही होता है, यानी, फसलकी कटनीके बाद वर्षा आने तक प्रतिवर्ष करीब ४–५ महीने खेतों और जंगलोंमें करीब १२ करोड़ मजदूर निरुद्यम बैठे रहते है।

कीन्सके शब्दोंमें अिन मजदूरोंको 'विवश बेकार' (involuntary unemployed) कह सकते हैं।

भारतकी यह मौसमके अनुसार चलनेवाली 'विवश बेकारी' कितनी बड़ी है, पश्चिमके लोग अुसकी ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। संख्याकी दृष्टिसे देखें, तो ब्रिटेनमें खेतों, कार्यालयों या फेक्टरियोंमें अेक भी स्त्री या पुरुष दो साल तक काम न करे अैसा माना जाय, तो हमें भारतकी अिस भयानक आर्थिक समस्याकी विशालताका कुछ अन्दाजा मिलेगा।

अिस तरह खयाल कीजिये कि अिस बेकारीसे भारतकी जनताको कितना शारीरिक और मानसिक त्रास होता होगा।

कीन्सने भारतमें फैली हुअी अिस विशेष प्रकारकी बेकारीका विचार तो नहीं किया, लेकिन अर्थशास्त्रीके नाते अुनकी आरंभिक प्रवृत्तियोंसे भारतका काफी सम्बन्ध था।

सिविल सर्विसमें जाने पर अुनकी पहली नियुक्ति अिण्डिया आफिसमें ही हुअी थी। अुनकी पहली प्रकाशित रचनाओंका विषय भारत ही है। अिन रचनाओंमें 'भारतीय मुद्रा और व्यावसायिक पूंजी' नामकी अेक पुस्तक है, जो १९१३ में प्रकाशित हुअी थी, 'भारतमें हालमें हुअी कुछ आर्थिक घटनायें' नामक अेक लेख है, जो मार्च, १९०९ के 'अिकॉनामिक जरनल' नामक सामयिकमें निकला था, और १९११ में प्रकाशित 'भारतमें आर्थिक परिवर्तन' नामक पुस्तककी समालोचना है।

अिस आलोचनाका अेक अंश अिस प्रकार है, "लेखक अेक पूर्वी देशके बारेमें लिख रहा है, लेकिन अुसकी आर्थिक कसौटियां पश्चिमकी हैं। किसी राष्ट्रकी साधन-सम्पत्तिका अुत्तम विनियोग और अुपयोग जिन परिस्थितियों पर निर्भर होता है, अुनका अुसे पूरा ज्ञान नहीं है। पुस्तकमें बम्बअी और कलकत्ताकी मिलों पर अुचितसे अधिक ध्यान दिया गया है।"

आगे चलकर वे कहते हैं कि अिन मिलोंसे भारतकी सुख-समृद्धिमें शायद ही कोअी मदद हो सकती है। अुसका निर्माण तो भारतकी बुद्धि और पूंजीका अुपयोग अुसके खेतों और गांवों पर करनेसे ही होगा। कहनेकी जरूरत नहीं कि यह बात आज भी अुतनी ही सही है, जितनी सन् १९११ में थी।

५

बचतके खिलाफ दो दुष्ट चक्र कार्य करते हैं। मौसममें मिलने वाले खेतीके कामसे आय बहुत थोड़ी होती है, और अुससे साल-भरका खर्च चलाना पड़ता है, अिसलिअे बचत कुछ नहीं होती। चूंकि बचत नहीं होती अिसलिअे सुधारोंके लिअे जो पूंजी चाहिये वह नहीं मिलती और सुधारोंके विना अुत्पादन तथा आय बढ़ नहीं सकती।

दूसरा दुष्ट चक्र पहलेमें से ही अुत्पन्न होता है। बोनेसे लगाकर फसल आने तकके समयका अिन्तजाम करनेके लिअे किसानोंको ऋण चाहिये।

चूंकि यह आवश्यकता पूरी करने लायक बचत होती ही नहीं है, अिसलिअे ऋणके लिअे बहुत अूंचा ब्याज चुकाना पड़ता है।

अिस तरह बचतके अभावमें अूंची ब्याज-दर देना पड़ती है, अूंची ब्याज-दरके कारण किसानोंकी आय कम होती है, और कम आयके कारण बचतके लिअे अवकाश नहीं होता; और फिर बचतकी कमीमें अूंची ब्याज-दर देना पड़ती है।

अिन असंख्य बेकारोंके लिअे भारतके पास कोअी अैसा अुद्योग नहीं जिसके जरिये वह अुन्हें काम दे सके। गांव पूरी तरह शहरों पर अवलम्बित हैं।

कर्ज जो मुश्किलसे मिलता है और जिसके लिअे अुन्हें अितना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, शहरोंसे आता है।

गांवोंमें पैदा होनेवाली वस्तुओंकी गांववालोंको बहुत कम कीमत मिलती है, और वे सब शहरोंमें बिकती हैं। नयी आपत्तियोंके खिलाफ कीन्सके बताये हुअे रक्षाके अुपायों पर अमल किया जाय, अुसके पहले भारतमें फैली हुअी बेकारीको कम करनेकी जरूरत है।

खर्च बढ़ानेकी कीन्सकी पद्धतिकी खास बात यह है कि वह बेकारीके खिलाफ तभी सफल होती है, जब अुसका अुपयोग बड़े प्रमाण पर और बेकारी फैलनेके पहले किया जाय।

कीन्स यह मानकर चलते हैं कि मजदूर वर्ग गतिशील है — अेक धन्धा छोड़कर दूसरे धन्धेमें जल्दी लग सकता है और बहुत-सी पूंजी बेकार पड़ी हुअी है। लेकिन भारतकी अवस्था अिससे भिन्न है; वहां पूंजीकी कमी है और अुसकी बेकार जनता अपनी जगह पर दुःखसे बंधी हुअी पड़ी है, वहांसे हट नहीं सकती है।

www.vinoba.in

भारतके लिअे तो असे अुपायोंकी जरूरत है, जो बेकारोंको काम दें, पूंजीकी जरूरत कम करें, गांवोंमें स्वावलम्बनके जरिये जीवन-मान बढ़ायें और हिंसाका खतरा कम करें — जिसे गांधी बहुत महत्त्व देते थे।

जो माल कम है अुसकी मांगसे हिंसा पैदा होती है। अिसलिअे जिसका अुत्पादन बढ़ाकर मांग पूरी की जा सकती है, अुसे तरजीह देनी चाहिये।

गांधीके अर्थशास्त्रमें कमी (scarcity)को निर्णायक महत्त्व प्राप्त है, अुत्पादन पर लगनेवाले खर्च या कार्यक्षमताको नहीं।

अभी हालमें जो परिस्थितियां प्रकाशमें आयी हैं, अुन्हें देखते हुअे अिस नीतिका महत्त्व प्रगट होता है। असा मालूम हुआ है कि आवश्यक वस्तुओंकी तंगी दुनियाके अुत्पादन, व्यापार और सबको पूरा काम देनेके लक्ष्यके लिअे खतरा पैदा करनेवाली है।

अिस परिस्थिति पर काबू पानेके लिअे गांधीकी स्थानीय साधन-सम्पत्तिका अुपयोग करनेकी सूचना जरूर सहायक हो सकती है।

गांधीके अनुसार हल चलानेके लिअे तेलकी बजाय बैलोंका आश्रय लेना अधिक हितकर है, क्योंकि अगर भारत अेक बार बैलोंका आश्रय छोड़ दे, तो तेल न मिलनेकी परिस्थिति अुत्पन्न होने पर अुसे विनाशका ही मुकाबला करना पड़ेगा।

अन्नके अुत्पादनमें कार्य-शक्तिके साधनोंकी तरह जो महत्त्व बैलों और मनुष्योंका है, वही कपड़ेके अुत्पादनमें चरखेका है।

कपड़ेकी मिलें अपना कपड़ा बेचनेके लिअे बाजारों पर और लोहा, विदेशी रुअी और सूत आदि असी सामग्री पर निर्भर करती हैं, जिनमें तंगीकी स्थिति आ सकती है।

लेकिन चरखेके लिअे लगनेवाली सामग्रीकी अुचित व्यवस्था हो सकती है।

चरखा स्थानिक अुत्पादन करता है और स्थानिक साधनों तथा बाजारों पर आधार रखता है। अिसलिअे अुसमें धोखा, सट्टा, संघर्ष और हिंसाकी संभावना बहुत कम हो जाती है।

चूंकि मिलोंका कपड़ा खरीदनेमें जो पैसा लगता था वह अब बचेगा, अिसलिअे गांववालोंको कर्जकी अुतनी आवश्यकता नहीं रहेगी तथा अुतनी हद तक वे ब्याजसे भी मुक्त हो जायंगे।

चरखा बेकारोंके व्यर्थ जानेवाले घंटोंका अुपयोग करेगा और अुनकी नैतिक अवनतिको रोकेगा।

अिस तरह चरखा भारतकी ग्रामीण जनताके दुःखोंका सबसे बड़ा निवारक सिद्ध होता है। वह भारतके गांवोंमें बसनेवाली असंख्य जनताको विनाशसे बचानेवाला साधन है।

गांधी जोर देकर कहते थे कि जिसे कोअी दूसरा अधिक आमदनीवाला काम मिलता है, वह अुसे छोड़कर चरखा अपनावे, असा मेरा मतलब नहीं है :—

"चरखेके लिअे मेरा अितना ही दावा है कि खेतीके साथ कोअी अुपयोगी पूरक अुद्योग न होनेके कारण भारतकी जनताके अेक बड़े भागको सालमें लगभग ६ माह मजबूरन बेकार रहना पड़ता है और परिणामस्वरूप भूखों मरना पड़ता है। यह भारतकी सबसे बड़ी समस्या है और चरखा ही अुसका अेकमात्र तात्कालिक, व्यावहारिक और स्थायी हल है।"

अुसी सिलसिलेमें वे आगे कहते हैं, "अगर ये दो बातें न होतीं तो भारतके राष्ट्रीय जीवनमें चरखेका कोअी स्थान न होता।"

* * *

चरखेने अेक काम और किया। शरीर-श्रमको बौद्धिक श्रम या यंत्र-श्रमसे हलके दर्जेका माना जाता है; अिसके सिवा बेकारी और भुखमरीके स्थायी वातावरणमें लोगोंका जो नैतिक ह्रास होता है, अुनके मनमें जो अुदासीनता घर कर लेती है, अुसके कारण शरीर-श्रमका मूल्य गिर जाता है। अिन परिस्थितियोंमें चरखेने शरीर-श्रमकी प्रतिष्ठा जमानेका काम किया, वह शरीर-श्रमका प्रतीक बन गया।

जहां पश्चिमके लोग अुसे औद्योगिक पिछड़ेपन, अक्षम अुत्पादन और यांत्रिक प्रगतिके निंदनीय विरोधका प्रतीक मानेंगे, वहां गांधीकी नजरमें वह निष्क्रियता पर कार्यकी, निर्जीवता पर जीवनकी, बिखरने और विनष्ट होनेकी प्रक्रिया पर कुटुम्ब-संस्था और ग्राम-समाजकी अेकताकी विजयका चिन्ह था।

चरखा अहिंसाकी विजय सूचित करता है। अेक बार जब किसीने गांधीसे कहा, "मुझे अीश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन कराअिये", तो अुन्होंने अुत्तर दिया, "तुम्हें वह चरखेमें मिलेगा।"

पश्चिमके विचार भारतकी परिस्थितियोंके अनुकूल बनें, अिसके लिअे अुनमें सुधार करनेकी आवश्यकता होगी।

जिस देशमें असंख्य बेकार पड़े हुअे हैं, वहां अुद्योगोंमें मजदूरीकी बचत करनेवाले यंत्रोंका बाहरसे आयात करने या देशमें ही बनानेके लिअे अपनी दुर्लभ साधन-सामग्री खर्च करनेको क्या सही अर्थनीति कह सकते हैं?

गांधीका अुत्तर था कि असी परिस्थितियोंमें सच्ची अर्थनीति गृह-अुद्योगकी ही हो सकती है। ग्रामवासी गृह-अुद्योग चलायेंगे या स्थानीय कच्चे मालका अुपयोग करके साबुन, आटा, कागज आदि बनायेंगे।

लेकिन अिन गृह-अुद्योगोंके बाद भी काफी बेकारी बच रहती है। असे बेकारोंको काममें लगानेके लिअे छोटे पैमानेके ग्रामोद्योग शुरू करने होंगे।

* * *

यह सवाल अुठता है कि यह व्यवस्था गांधीके विचारोंके साथ मेल खाती है या नहीं? गृह-अुद्योगोंके स्वरूप और अुद्देश्यके विषयमें बहुत कुछ भ्रम तो अिसलिअे पैदा होता है कि मशीनके प्रति गांधीके दृष्टिकोणका यथेष्ट विश्लेषण नहीं किया गया है।

गांधी अेक समय हर प्रकारके यंत्रके खिलाफ थे। वे अुसे आधुनिक सभ्यताकी अेक प्रधान वस्तु और महापाप जैसा मानते थे। लेकिन बादमें अुनके दृष्टिकोणमें काफी परिवर्तन हो गया था। अुन्होंने कहा था, "जो काम करना है, अुसे करनेके लिअे जब मनुष्योंकी संख्या कम हो, तब यंत्रीकरण ठीक है। लेकिन कामके लिअे जितने चाहिये अुससे ज्यादा आदमी मिलते हों, तब वह अनिष्ट है।"

जब वह बहुतोंको नुकसान पहुंचाकर थोड़ेसे लोगोंको मालामाल करता हो, तब वह खराब है। किन्तु यदि अुसका अुपयोग सारी जनताकी भलाअीके लिअे हो तो वह अच्छा है।

[५-८-'५३ के 'अिन्डियन अेक्सप्रेस' से] अेस० मूस
(अंग्रेजीसे)

विषय-सूची

		पृष्ठ
आचार्य कृपलानीसे विनती	मगनभाअी देसाअी	२४९
भूदान-यज्ञ क्यों और कैसे?	श्रीकृष्णदास जाजू	२५०
शराबबंदी रद्द नहीं की जा सकती	स्वामी सीताराम	२५१
बेकारी	भारतन् कुमारप्पा	२५२
बापू और जमीनकी समस्या	सुरेश रामभाअी	२५३
गांधी, कीन्स और चरखा	अेस० मूस	२५४

www.vinoba.in